

करेंट अफेयर्स

उत्तराखंड

(संग्रह)



जनवरी

2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड

➤ CM धामी ने देहरादून-मसूरी ट्रेक का निरीक्षण किया	3
➤ अनियंत्रित निर्माण से उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा	4
➤ प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने का आमंत्रण	5
➤ उत्तराखंड में लैंडस्लाइड डैम	7
➤ उत्तराखंड में सोपस्टोन खनन	8
➤ प्रधानमंत्री 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे	10
➤ उत्तराखंड में GST पंजीकरण में छूट प्रदान	11
➤ उत्तराखंड में कड़े पंजीकरण मानदंडों के साथ समान नागरिक संहिता लागू	12
➤ उत्तराखंड में दसवीं कक्षा के छात्रों के लिये 10 विषय अनिवार्य होंगे	14
➤ 38वें राष्ट्रीय खेल	15
➤ उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता नियम	18
➤ केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य	19
➤ उत्तरकाशी में भूकंप	20
➤ एशियाई जलपक्षी जनगणना	22
➤ उत्तराखंड ने UCC लागू किया और पोर्टल लॉन्च किया	23
➤ 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिये अवसंरचना का विकास	24
➤ उत्तराखंड में वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण	24

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

उत्तराखंड

CM धामी ने देहरादून-मसूरी ट्रेक का निरीक्षण किया

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-6 के हालिया आँकड़ों से उत्तर प्रदेश में चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चलता है, जहाँ हर चार में से एक व्यक्ति उच्च रक्तचाप के खतरे में है।

- यह स्वास्थ्य स्थिति, जिसे प्रायः “साइलेंट किलर” कहा जाता है, स्ट्रोक और दिल के दौरों जैसी गंभीर जटिलताओं को जन्म देने की क्षमता के कारण एक बड़ा खतरा उत्पन्न करती है।

मुख्य बिंदु

- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने पाया है कि उपचार चाहने वाले रोगियों में से लगभग 25% उच्च रक्तचाप का खतरा है।
- चिंताजनक बात यह है कि इनमें से कई व्यक्ति अपनी स्थिति से अनभिज्ञ हैं, जिससे उनमें मस्तिष्क आघात और हृदयाघात जैसी गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
- इसके उत्तर में, AIIMS ने उच्च रक्तचाप का शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन में सुविधा प्रदान करने के लिये रोगियों और उनके देखभालकर्ताओं पर व्यापक डेटा संग्रह शुरू किया है।
- सामान्य रक्तचाप में उतार-चढ़ाव और उच्च रक्तचाप के बीच अंतर।
- जबकि युवा वयस्कों के लिये सामान्य रक्तचाप रीडिंग आमतौर पर 120/80 mmHg के आसपास होती है, 140/90 mmHg या इससे अधिक की रीडिंग उच्च रक्तचाप का संकेत है।
- नियमित निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मामूली वृद्धि भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है।
- इस बढ़ती स्वास्थ्य चिंता से निपटने के लिये AIIMS भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के साथ सहयोग कर रहा है।
- इस साझेदारी का उद्देश्य रोगियों और उनके परिवारों पर व्यापक डेटा एकत्र करना है, जिसमें रक्तचाप संबंधी समस्याओं, उच्च रक्तचाप और मधुमेह की व्यापकता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- इसका लक्ष्य पैटर्न और जोखिम कारकों की पहचान करना है, ताकि उच्च रक्तचाप को प्रभावी ढंग से रोकने और प्रबंधित करने के लिये लक्षित हस्तक्षेप संभव हो सके।
- NFHS रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में उच्च रक्तचाप के बढ़ते जोखिम की गंभीरता को उजागर करती है।
- इसमें इस स्थिति से जुड़े प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिये जागरूकता बढ़ाने, नियमित स्वास्थ्य जाँच और शीघ्र चिकित्सा की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



उच्च रक्तचाप

परिचय:

- ◆ पहली (सिस्टोलिक) संख्या हृदय के सिकुड़ने या धड़कने के समय रक्त वाहिकाओं में दबाव को दर्शाती है।
- ◆ दूसरी (डायस्टोलिक) संख्या, धड़कनों के बीच हृदय के विश्राम के समय वाहिकाओं में दबाव को दर्शाती है।
- ◆ उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर) तब होता है जब आपकी रक्त वाहिकाओं में दबाव बहुत अधिक (140/90 mmHg या उससे अधिक) हो जाता है। यह सामान्य है लेकिन अगर इसका उपचार न किया जाए तो यह गंभीर हो सकता है।
- ◆ रक्तचाप को दो संख्याओं के रूप में लिखा जाता है:
- ◆ उच्च रक्तचाप के संबंध में जागरूकता बढ़ाने तथा लोगों को इस मूक हत्यारे को रोकने और नियंत्रित करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु हर वर्ष 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है।
- भारत पर उच्च रक्तचाप का बोझ
 - ◆ केवल भारत में 30-79 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 188.3 मिलियन वयस्क उच्च रक्तचाप से जूझ रहे हैं।
 - ◆ भारत में उच्च रक्तचाप की व्यापकता वैश्विक औसत 31% से थोड़ी कम है।
 - ◆ 50% नियंत्रण दर तक पहुँचने के लिये, भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित अतिरिक्त 67 मिलियन लोगों को प्रभावी उपचार प्राप्त हो।
 - ◆ यदि प्रगति के लक्ष्यों को प्राप्त किया गया, तो वर्ष 2040 तक उच्च रक्तचाप के कारण होने वाली 4.6 मिलियन मौतों को रोका जा सकता है।

अनियंत्रित निर्माण से उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा

चर्चा में क्यों ?

देहरादून में रियल एस्टेट का तेजी से विस्तार पारिस्थितिकी क्षरण और जैव विविधता हानि के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताएँ उत्पन्न कर रहा है।

- राजपुर और मसूरी रोड पर बड़ी आवासीय परियोजनाओं के कारण निजी और सार्वजनिक दोनों ही भूमि पर अतिक्रमण की सूचना मिली हैं, जिसके कारण हरित क्षेत्र नष्ट हो रहा है और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है।

मुख्य बिंदु

- निर्माण गतिविधियों में वन भूमि और निजी भूखंडों को साफ किया जा रहा है, जिनमें रिस्पना नदी तक जाने वाले प्राकृतिक निकासी प्रणाली (प्राकृतिक नालों) वाले क्षेत्र भी शामिल हैं।
- घाटियों को कीचड़ से भर दिया जा रहा है, जो वर्षा के दौरान बह जाता है तथा देशी वृक्षों को हटाने से स्थानीय जैव विविधता बाधित होती है तथा विकास क्षेत्र की वहन क्षमता से अधिक हो रहा है।
- अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों के कारण राजपुर रिज क्षेत्र में जल स्रोत और नदियाँ नष्ट हो गई हैं तथा प्राकृतिक वनस्पति का स्थान शहरी विकास ने ले लिया है।
- ◆ यह स्थिति विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिये सतत् शहरी नियोजन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- ऊँचे क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण के कारण अक्सर निचले क्षेत्रों में **मलबा** और **भूस्खलन** होता है, जिससे निवासियों और पर्यावरण को खतरा होता है।
- इन चुनौतियों से निपटने के लिये, विशेषज्ञ भवन निर्माण नियमों को लागू करने, **पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)** करने और ज़िम्मेदार निर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देने के महत्त्व पर जोर देते हैं।
 - ◆ उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों की पारिस्थितिक अखंडता को संरक्षित करने वाले सतत् विकास की वकालत करने में जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी भी महत्वपूर्ण है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)

- EIA एक संरचित पद्धति है जिसका उपयोग आगामी परियोजनाओं या गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण करने और समझने के लिये किया जाता है।
 - ◆ इससे यह मूल्यांकन और पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलती है कि इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले इनका प्राकृतिक परिवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
- EIA की अवधारणा 1960 और 1970 के दशक में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में बढ़ती चिंताओं की प्रतिक्रिया के रूप में उभरी।
- 27 जनवरी, 1994 को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने पहली EIA अधिसूचना जारी की।
 - ◆ 1972 में स्टॉकहोम में **मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन** एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसमें निर्णय लेने में पर्यावरणीय मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया गया।
 - ◆ अन्य उल्लेखनीय समझौतों में **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)** और **जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)** शामिल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार करने के महत्त्व पर प्रकाश डालते हैं।

प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने का आमंत्रण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को **राष्ट्रीय खेलों** में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया, जो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक राज्य में आयोजित किये जाएंगे। यह पहली बार है जब उत्तराखंड इस आयोजन की मेज़बानी कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री को भेंट किये गये उपहार:
 - ◆ मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मुलाकात के दौरान चमोली जिले के **मलारी कारीगरों** द्वारा निर्मित एक शॉल तथा **नारायण आश्रम की** प्रतिकृति भेंट की।
- परियोजनाओं के बारे में:
 - ◆ विकास अद्यतन:
 - उन्होंने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में चल रही विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी।
 - उन्होंने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के प्रथम चरण की तीव्र प्रगति पर प्रकाश डाला।
 - उन्होंने टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना के लिये सर्वेक्षण पूरा होने का भी उल्लेख किया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
कलासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- उन्होंने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में **जल जीवन मिशन** की प्रगति से अवगत कराया।
- उन्होंने **पुराने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को बंद करने** और सभी ट्रेनों को **नए योग नगरी रेलवे स्टेशन से संचालित करने** का भी प्रस्ताव रखा।
- ◆ यह सुझाव दिया गया कि यातायात में सुधार के लिये पुराने स्टेशन की भूमि को नई सड़क प्रणाली के लिये पुनः उपयोग में लाया जाए।
- **ऋषिकेश एक प्रतिष्ठित शहर के रूप में:**
 - ◆ मुख्यमंत्री ने रिवर राफ्टिंग के लिये प्रतिष्ठित शहर के रूप में ऋषिकेश को चुनने के लिये आभार व्यक्त किया।
 - ◆ उन्होंने राज्य के सीमित संसाधनों के कारण **हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर** और **शारदा कॉरिडोर परियोजना** के लिये केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया।
- **भूतापीय ऊर्जा परियोजना:**
 - ◆ उन्होंने बताया कि **उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा** के दोहन के लिये **आइसलैंड दूतावास** के साथ एक समझौता ज्ञापन प्रस्तावित है।
 - ◆ उन्होंने **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** तथा **विदेश मंत्रालय** से आवश्यक अनापत्ति पत्र प्राप्त होने की पुष्टि की।
 - ◆ उन्होंने परियोजना के लिये तकनीकी और वित्तीय सहायता का भी अनुरोध किया ताकि उत्तराखंड को **वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन** लक्ष्य में योगदान करने में मदद मिल सके।
- **सड़क परिवहन प्रस्ताव:**
 - ◆ मुख्यमंत्री ने सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजे गए विभिन्न सड़क परिवहन प्रस्तावों के लिये मंजूरी मांगी। इनमें शामिल हैं:
 - ◆ ऋषिकेश बाईपास
 - ◆ हरिद्वार बाईपास (पैकेज 2)
 - ◆ **देहरादून-मसूरी कनेक्टिविटी**
 - ◆ देहरादून रिंग रोड
 - ◆ चंपावत बाईपास
 - ◆ लालकुआँ, हलद्वानी और काठगोदाम बाईपास
 - ◆ **मानसखंड परियोजना**

राष्ट्रीय खेल

- **पृष्ठभूमि:**
- वर्ष 1924 में अविभाजित पंजाब के लाहौर में **भारतीय ओलंपिक खेलों** का **पहला संस्करण** आयोजित किया गया।
- भारतीय ओलंपिक खेलों को वर्ष 1940 में **राष्ट्रीय खेलों** का नाम दिया गया था। इस प्रतियोगिता में कई भारतीय राज्यों के एथलीट विभिन्न खेल विधाओं में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- ओलंपिक आंदोलन, जिसने **1920 के दशक** में राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया, में **राष्ट्रीय खेल शामिल हैं**। भारत में **राष्ट्रीय खेलों** की कल्पना पहले भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में की गई थी जिसका लक्ष्य राष्ट्र में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देना था।
- **उद्देश्य:**
- ये भारतीय एथलीटों, खेल संगठनों आदि के लाभ के लिये आयोजित किये जाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं।
- इसका उद्देश्य खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिये बड़ी संख्या में युवाओं को आकर्षित करना है।
- इसका उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों में खेल संस्कृति को विकसित करना तथा उन्हें स्वस्थ समाज के निर्माण में खेलों के महत्त्व के बारे में शिक्षित करना है।
- क्षेत्राधिकार:
- राष्ट्रीय खेलों की अवधि और नियम पूरी तरह से भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकार क्षेत्र में हैं।

उत्तराखंड में लैंडस्लाइड डैम

चर्चा में क्यों ?

IIT रूड़की द्वारा हाल ही में किये गए एक अध्ययन में गढ़वाल क्षेत्र से होकर बहने वाली अलकनंदा नदी को भूस्खलन से प्रेरित प्राकृतिक बाँधों के लिये सबसे अधिक संवेदनशील बताया गया है। इस अध्ययन का शीर्षक है 'भारत के उत्तराखंड में भूस्खलन बांध अध्ययन: अतीत, वर्तमान और भविष्य' और इसे स्पिंगर द्वारा प्रकाशित किया गया है।

- इसमें रेखांकित किया गया है कि इस तरह के बाँधों के प्रति संवेदनशीलता के मामले में अलकनंदा के बाद मंदाकिनी, धौलीगंगा और भागीरथी नदियाँ हैं।

प्रमुख बिंदु

- अध्ययन के निष्कर्ष:
 - ◆ उत्तराखंड का भूभाग:
 - ◆ उत्तराखंड की संकरी घाटियाँ इसे भूस्खलन-प्रेरित प्राकृतिक बाँधों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती हैं, जो नदियों को अवरुद्ध करते हैं और ऊपरी भाग झीलें बनाते हैं।
 - ◆ इन अवरोधों के कारण भूस्खलन झील के फटने से बाढ़ (LLOF) का बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिसके परिणाम भयावह हो सकते हैं।
 - ◆ सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र:
 - ◆ भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित बाँधों में चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी शामिल हैं।
 - ◆ चमोली में गोहना ताल का टूटना क्षेत्र की सबसे गंभीर लैंडस्लाइड डैम की घटना है, जिसका असर हरिद्वार तक के निचले इलाकों पर पड़ा था।
 - ◆ लैंडस्लाइड डैम का ऐतिहासिक संदर्भ:
 - ◆ उत्तराखंड में लैंडस्लाइड डैम का इतिहास 29,000 से 19,000 वर्ष पूर्व के लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम (LGM) काल से जुड़ा है।
 - ◆ 19वीं शताब्दी में लैंडस्लाइड डैम महत्वपूर्ण घटनाएँ दर्ज की गई हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय 1970 में गोहना झील का टूटना है, जिसके दीर्घकालिक प्रभाव हुए।
 - ◆ वर्तमान प्रवृत्ति और चिंताएँ:
 - ◆ अध्ययन से पता चलता है कि लैंडस्लाइड डैम की घटनाओं का चरम महीना अगस्त है, जो मानसून के साथ सुमेलित है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, सड़क निर्माण और जल विद्युत परियोजनाओं ने हाल के दशकों में ऐसी घटनाओं की आवृत्ति को बढ़ा दिया है।
- ◆ जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी:
- ◆ यद्यपि वर्ष 2018 के बाद से बड़ी घटनाएँ कम हुई हैं, फिर भी अध्ययन में भविष्य के जोखिमों को कम करने के लिये तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- ◆ भूस्खलन बाँधों की अस्थिरता, विशेषकर संकीर्ण घाटियों में, आपदा प्रबंधन के लिये महत्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।
- ◆ भूस्खलन के प्रमुख कारण:
- ◆ अत्यधिक वर्षा और बादल फटने को भूस्खलन के प्रमुख कारणों के रूप में पहचाना गया है।
- ◆ मलबे का प्रवाह भूस्खलन का सबसे आम प्रकार है, जो उत्तराखंड की पहाड़ियों में नदियों के प्रवाह को अवरुद्ध करने के लिये जिम्मेदार है।

अलकनंदा नदी

- यह गंगा की मुख्य धाराओं में से एक है।
- यह उत्तराखंड में सतोपथ और भागीरथ ग्लेशियरों के संगम और तलहटी से निकलती है।
- यह देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है जिसके बाद इसे गंगा कहा जाता है।
- इसकी मुख्य सहायक नदियाँ मंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडर हैं।
- अलकनंदा प्रणाली चमोली, टिहरी और पौड़ी जिलों के कुछ हिस्सों को जल प्रदान करती है।
- हिन्दू तीर्थस्थल बद्रीनाथ और प्राकृतिक झरना तप्त कुंड अलकनंदा नदी के तट पर स्थित हैं।

भागीरथी नदी

- यह उत्तराखंड की एक अशांत हिमालयी नदी है, और गंगा की दो मुख्य धाराओं में से एक है।
- भागीरथी नदी 3892 मीटर की ऊँचाई पर, गौमुख में गंगोत्री ग्लेशियर के तल से निकलती है और 350 किलोमीटर चौड़े गंगा डेल्टा में विस्तृत होके अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- भागीरथी और अलकनंदा गढ़वाल में देवप्रयाग में मिलती हैं और उसके बाद गंगा के नाम से जानी जाती हैं।

धौलीगंगा

- इसका उद्गम वसुधारा ताल से होता है, जो संभवतः उत्तराखंड की सबसे बड़ी हिमनद झील है।
- धौलीगंगा अलकनंदा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है, दूसरी नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी हैं।
- धौलीगंगा रैणी में ऋषिगंगा नदी से मिलती है।

उत्तराखंड में सोपस्टोन खनन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में सोपस्टोन खनन को विनियमित करने में विफल रहने के लिये अधिकारियों की आलोचना की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- पर्यावरणीय चिंता:
 - ◆ भूमि अवतलन:
 - उत्तराखंड में **भू-धँसाव** एक गंभीर समस्या है, जो बागेश्वर के कांडा-कन्याल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण और भी गंभीर हो गई है।
 - खनन कार्य, **मृदा अपरदन**, संसाधनों का निष्कासन और **भूकंप** इस समस्या को बढ़ाते हैं।
 - ◆ ढलान अस्थिरता:
 - निचली ढलानों पर खनन से **संरचनात्मक अखंडता दुर्बल** होती है, जिससे ऊपरी ढलानों पर स्थित गाँव प्रभावित होते हैं।
 - दोमट और ढीली मृदा से कटाव की संभावना बढ़ जाती है, विशेषकर **मानसून के दौरान**।
 - ◆ अपर्याप्त सुरक्षा उपाय:
 - हरित पट्टियों, अवरोधक दीवारों, बफर जोन, ढलान निगरानी और सुरक्षात्मक संरचनाओं का अभाव कटाव को बढ़ाता है।
 - **जल और वायु प्रदूषण:**
 - खनन गतिविधियों के कारण क्षेत्र में **जल की कमी**, प्रदूषण और **वायु प्रदूषण** होता है।
 - ◆ सांस्कृतिक चिंताएँ:
 - पारंपरिक वास्तुकला पर प्रभाव:
 - भूमि धँसने से **कुमाऊँनी बाखली आवास स्थानों को नुकसान पहुँचा है**, जो ऐतिहासिक रूप से भूकंपरोधी क्षमता रखते थे।
 - ◆ विरासत को क्षति:
 - सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व के 10वीं सदी के स्थल कांडा में **कालिका मंदिर के फर्श** में दरारें खनन से संबंधित गिरावट का संकेत देती हैं।
 - लोक संगीत, नृत्य और **हस्तशिल्प** सहित क्षेत्र की सांस्कृतिक प्रथाएँ भी प्रभावित होती हैं।
 - ◆ प्रशासनिक चूक:
 - राज्य और केंद्र सरकारें “अर्द्ध-यंत्रीकृत खनन” को परिभाषित करने में विफल रहीं, फिर भी उन्होंने ऐसी गतिविधियों के लिये पर्यावरणीय मंजूरी दे दी।
 - स्पष्ट नीतिगत सीमाओं के बिना भारी उपकरणों के उपयोग से स्थिति और खराब हो गई है।

सोपस्टोन

- सोपस्टोन एक नरम रूपांतरित चट्टान है जो टैल्क तथा **क्लोराइट**, **डोलोमाइट** और **मैग्नेसाइट** की भिन्न-भिन्न मात्राओं से बनी होती है।
- उपयोग:
 - ◆ सोपस्टोन का उपयोग इसकी स्थायित्व और सौंदर्य अपील के कारण उद्योगों में **मूर्तियाँ**, काउंटरटॉप्स, सिंक और टाइलें बनाने के लिये व्यापक रूप से किया जाता है।
 - ◆ इसकी उत्कृष्ट ऊष्मा प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग **स्टोव**, **फायरप्लेस** और **प्रयोगशाला काउंटरटॉप्स** में किया जाता है।
 - ◆ **पिसा हुआ सोपस्टोन कागज**, **सौंदर्य प्रसाधन** और **पेंट** में भराव के रूप में काम आता है।
 - ◆ इसका उपयोग **बर्तन**, **हस्तशिल्प** और **मूर्तियाँ बनाने** के लिये भी किया जाता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- भारत में उपलब्धता:
 - ◆ भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार, राजस्थान (57%) और उत्तराखंड (25%) में महत्वपूर्ण भंडार हैं।
 - ◆ राजस्थान: सबसे बड़ा उत्पादक, विशेष रूप से उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा क्षेत्र में।
 - ◆ उत्तराखंड: बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में उल्लेखनीय जमा।
 - ◆ तमिलनाडु और कर्नाटक: यहाँ भी छोटे भंडार मौजूद हैं।

प्रधानमंत्री 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने जा रहे हैं।

मुख्य बिंदु

- खेलों का परिचय:
 - ◆ भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने उत्तराखंड को 2025 राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी के लिये घोषित किया है।
 - ◆ राज्य के कई शहरों में 38 खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हुए 10,000 से अधिक एथलीट, अधिकारी और कोच भाग लेंगे।
- भारतीय खेलों के लिये ऐतिहासिक घटना:
 - ◆ IOA अध्यक्ष पीटी उषा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों को भारत में पारंपरिक और आधुनिक खेलों को बढ़ावा देने के लिये एक महत्वपूर्ण आयोजन बताया।
 - ◆ कलरीपयट्टू, योगासन, मल्लखंब और राफिटिंग जैसे प्रदर्शनकारी खेलों को शामिल करना भारत की समृद्ध विरासत के प्रति श्रद्धांजलि है तथा उभरते हुए एथलीटों के लिये एक अवसर है।
- राष्ट्रीय खेलों का परिचय:
 - ◆ राष्ट्रीय खेल एक ओलंपिक शैली का आयोजन है जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट पदक के लिये प्रतिस्पर्धा करते हैं।
 - ◆ वर्ष 2025 के संस्करण में 32 मुख्य खेल विधाएँ और चार प्रदर्शन कार्यक्रम शामिल होंगे।
- पिछले संस्करण:
 - ◆ वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किये जायेंगे और पाँच शहरों - मापुसा, मडगांव, पंजिम, पोंडा, वास्को में आयोजित किये जायेंगे।
 - ◆ महाराष्ट्र 80 स्वर्ण सहित 228 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा।
 - ◆ गुजरात में वर्ष 2022 का आयोजन 2015 के बाद सात वर्ष के अंतराल के बाद इस आयोजन का पुनरुद्धार होगा।

कलरीपयट्टू

- यह मानव शरीर के प्राचीन ज्ञान पर आधारित एक मार्शल आर्ट है।
- इसकी उत्पत्ति तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान केरल में हुई थी। अब यह केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्रचलित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :



- जिस स्थान पर इस मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जाता है उसे 'कलारी' कहा जाता है। यह एक मलयालम शब्द है जिसका अर्थ है एक तरह का व्यायामशाला। कलारी का शाब्दिक अर्थ है 'खलिहान' या 'युद्ध का मैदान'। कलारी शब्द पहली बार **तमिल संगम साहित्य** में युद्ध के मैदान और युद्ध क्षेत्र दोनों का वर्णन करने के लिये आया है।
- इसे अस्तित्व में सबसे पुरानी युद्ध प्रणालियों में से एक माना जाता है।
- इन्हें आधुनिक कुंग-फू का जनक भी माना जाता है।

मल्लखंब

- मल्लखंब एक पारंपरिक खेल है, जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है, जिसमें एक जिमनास्ट एक ऊर्ध्वाधर स्थिर या लटकी हुई लकड़ी के खंभे, बेंत या रस्सी के साथ हवाई योग या जिमनास्टिक आसन और कुशती की पकड़ का प्रदर्शन करता है।
- मल्लखंब नाम मल्ला, जिसका अर्थ है पहलवान और खंब, जिसका अर्थ है खंभा से लिया गया है। शाब्दिक अर्थ "कुशती का खंभा" है, यह शब्द पहलवानों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले पारंपरिक प्रशिक्षण उपकरण को संदर्भित करता है।
- मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इस खेल के केंद्र रहे हैं।



उत्तराखंड में GST पंजीकरण में छूट प्रदान

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड सरकार ने सौर उद्यमियों को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत अनिवार्य वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण से छूट देकर उन्हें महत्वपूर्ण राहत देने की घोषणा की है।

- इस पहल का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना तथा राज्य भर में **नवीकरणीय ऊर्जा** परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना है।

मुख्य बिंदु

- उद्योग महानिदेशक एवं सिडकुल (उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड) के प्रबंध निदेशक ने प्रवासी सम्मेलन के दौरान इस निर्णय की जानकारी दी।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
कलासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ इस बात पर प्रकाश डाला गया कि यह छूट सौर परियोजना निवेशकों की लंबे समय से चली आ रही मांग के उत्तर में दी गई है, जिन्हें GST पंजीकरण आवश्यकताओं के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा था।
- मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत हजारों सौर संयंत्र पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं और कई और पर काम चल रहा है।
- इससे पहले, सौर ऊर्जा को GST से छूट मिलने के बावजूद, उद्यमियों को सब्सिडी का दावा करने के लिये GST में पंजीकरण कराना पड़ता था।
- ◆ नई नीति इस चरण को समाप्त कर देती है, जिससे प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाती है तथा सौर परियोजना डेवलपर्स के लिये नौकरशाही संबंधी बाधाएँ कम हो जाती हैं।

उत्तराखंड सरकार का नवीकरणीय ऊर्जा विज्ञान:

- यह निर्णय अक्षय ऊर्जा और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- निवेश प्रक्रिया को सरल बनाकर, सरकार का लक्ष्य सौर ऊर्जा क्षेत्र में अधिक उद्यमियों को आकर्षित करना है, जिससे आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों में योगदान मिलेगा।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना

- उत्तराखंड ने सौर ऊर्जा खेती द्वारा स्वरोजगार के लिये 2020 में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की।
- इस योजना का उद्देश्य हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा उत्तराखंड के युवाओं और वापस लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।
- इस योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 25 किलोवाट के सौर संयंत्र आवंटित किये जाएँगे।

उत्तराखंड में कड़े पंजीकरण मानदंडों के साथ समान नागरिक संहिता लागू

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड सरकार 26 जनवरी, 2025 को समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसमें व्यक्तिगत और नागरिक मामलों से संबंधित पंजीकरणों के लिये कई अनिवार्य आवश्यकताएँ शामिल होंगी।

मुख्य बिंदु

- UCC पोर्टल
 - ◆ पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएँ निम्नलिखित हैं:
 - विवाह, तलाक और लिव-इन संबंधों का पंजीकरण।
 - लिव-इन रिश्तों की समाप्ति।
 - बिना वसीयत के उत्तराधिकार और कानूनी उत्तराधिकारी की घोषणा।
 - वसीयतनामा उत्तराधिकार।
 - अस्वीकृत आवेदनों के मामले में शिकायत पंजीकरण और अपील।
- व्यक्तिगत और सिविल मामलों के लिये विभिन्न आवश्यकताएँ शामिल हैं:
 - ◆ लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण:
 - मौजूदा और नए लिव-इन जोड़ों को अपने रिश्ते को पंजीकृत कराना होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

क्या है

समान नागरिक संहिता?

एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर



देश में हिंदू सिविल लॉ के दायरे में हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध आते

पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, तुर्की और इजिप्त जैसे कई देशों में लागू

संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी



गोवा में साल 1961 से समान नागरिक संहिता लागू है



- आवेदकों को आयु, राष्ट्रीयता, धर्म, फोन नंबर और पिछले संबंध की स्थिति का प्रमाण जैसे विवरण प्रदान करने होंगे।
- दोनों भागीदारों की तस्वीरें और घोषणाएँ अनिवार्य हैं।
- ऐसे रिश्तों में पैदा हुए बच्चों को जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर पंजीकृत किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

◆ विवाह और तलाक पंजीकरण:

- पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये UCC पोर्टल के माध्यम से विवाह और तलाक के लिये सख्त आवश्यकताएँ लागू की गई हैं।

◆ वसीयत उत्तराधिकार:

- घोषणाकर्ताओं को अपना, अपने उत्तराधिकारियों और गवाहों का आधार से जुड़ा विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- जालसाजी या विवाद को रोकने के लिये गवाहों को उत्तराधिकार घोषणा-पत्र पढ़ते हुए स्वयं की वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करना आवश्यक है।

◆ विवाह एवं रिश्तों के लिये शिकायत तंत्र:

- कोई तीसरा पक्ष UCC पोर्टल पर शिकायत के माध्यम से विवाह या लिव-इन रिलेशनशिप पर आपत्ति दर्ज करा सकता है।
- झूठे आरोपों का मुकाबला करने के लिये ऐसी शिकायतों का सत्यापन उप-पंजीयक द्वारा किया जाएगा।

समान नागरिक संहिता (UCC)

- समान नागरिक संहिता भारत के सभी नागरिकों के लिये विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक समूह को संदर्भित करती है।
- समान नागरिक संहिता की अवधारणा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
- हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य के लिये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है।

उत्तराखंड में दसवीं कक्षा के छात्रों के लिये 10 विषय अनिवार्य होंगे

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा तैयार किये गए एक मसौदे में प्रस्ताव दिया गया है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों को वर्तमान में पाँच विषयों के स्थान पर 10 अनिवार्य विषय पढ़ने होंगे।

- यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुरूप है।

मुख्य बिंदु

- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) ने राज्य पाठ्यक्रम ढाँचे का मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य शैक्षिक मानकों को बढ़ाना और छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिये बेहतर ढंग से तैयार करना है।
- नया पाठ्यक्रम 1986 की NEP के बाद पहला बड़ा कार्यान्वयन है, जो 1968 की नीति का उत्तराधिकारी था।
- विभिन्न समितियों के माध्यम से तैयार किये गए राज्य पाठ्यक्रम ढाँचे के मसौदे की राज्य सरकार द्वारा समीक्षा की जाएगी।
- इसमें केवल वे विषय शामिल हैं जिनकी अनुशंसा NEP द्वारा की गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को ये विषय लेना अनिवार्य होगा। उन्हें 11वीं कक्षा से ही विषय बदलने का विकल्प मिलेगा।
- इस नीति के तहत नए विषयों को शामिल करने से छात्रों में उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा मिलेगा। इनमें ब्यूटी एंड वेलनेस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और विभिन्न IT से संबंधी कार्यक्रम शामिल होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

- परिचय:
 - ◆ इससे पहले दो शिक्षा नीतियाँ 1968 और 1986 में लाई गई थीं।
 - NEP 2020 का लक्ष्य “भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना” है। यह स्वतंत्रता के बाद से भारत में शिक्षा के ढाँचे में तीसरा बड़ा बदलाव है।
- मुख्य विशेषताएँ:
 - ◆ पूर्व-प्राथमिक स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।
 - ◆ 3-6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना।
 - ◆ नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना (5+3+3+4) क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 वर्ष के आयु समूहों के अनुरूप है।
 - इसमें स्कूली शिक्षा के चार चरण शामिल हैं: आधारभूत चरण (5 वर्ष), प्रारंभिक चरण (3 वर्ष), मध्य चरण (3 वर्ष) और माध्यमिक चरण (4 वर्ष)।
 - ◆ कला और विज्ञान, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों, तथा व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है;
 - ◆ भारतीय भाषाओं और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने पर जोर,
 - ◆ एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, PARAKH (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिये ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना
 - ◆ वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिये एक अलग लिंग समावेशन निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र।

38वें राष्ट्रीय खेल

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, जो 28 जनवरी, 2025 से शुरू होंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़ा खेल आयोजन होगा, जिसमें पूरे भारत के खिलाड़ी 35 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे।

मुख्य बिंदु

- राज्य ने इस आयोजन के अनुरूप तीन महत्वपूर्ण प्रतीकों का अनावरण किया है: प्रतीक चिह्न, शुभंकर मौली और मशाल तेजस्विनी।
- ◆ ये प्रतीक उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, लुभावने परिदृश्य और अटूट भावना का सार दर्शाते हैं तथा राज्य की 25वीं वर्षगाँठ की गर्व और उत्सव के साथ चिह्नित करते हैं।
- ◆ यह खेल आयोजन न केवल एक भव्य प्रतियोगिता होगी, बल्कि उत्तराखंड के लिये राष्ट्र के समक्ष अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक पहचान को प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर भी होगा।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- लोगो (प्रतीक चिह्न):



- 38वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक लोगो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। इसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
 - ◆ हिमालय की चोटियाँ: राज्य की भव्यता और अनुकूलता का प्रतिनिधित्व करती हैं।
 - ◆ हिमालयी मोनाल: जैव विविधता और सांस्कृतिक गौरव पर प्रकाश डालता है।
 - ◆ गंगा नदी: पवित्रता और आध्यात्मिकता का एक पवित्र प्रतीक जो उत्तराखंड की पहचान का केंद्र है।
- शुभंकर मौली:
 - ◆ उत्तराखंड के राज्य पक्षी हिमालयन मोनाल के नाम पर रखा गया शुभंकर मौली इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, जीवंत वन्य जीवन और स्थायी भावना का प्रतीक है।
 - ◆ अपने चमकदार रंगों और सुंदरता के लिये जाना जाने वाला हिमालयी मोनाल, उत्तराखंड के प्राचीन पर्यावरण का प्रतीक है, जिसमें इसके राजसी पहाड़ से लेकर हरे-भरे जंगल शामिल हैं।
 - ◆ मौली उत्तराखंड के लोगों के दृढ़ संकल्प, ऊर्जा और दृढ़ता को दर्शाता है तथा उन गुणों को भी दर्शाता है जो एथलीट खेलों में लाते हैं।
 - ◆ मौली को शुभंकर के रूप में चुनकर राज्य प्रकृति के साथ अपने सामंजस्यपूर्ण संबंध और अपने लोगों की दृढ़ता का जश्न मनाता है, जिससे यह राष्ट्रीय खेलों का उपयुक्त प्रतीक बन जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- मशाल तेजस्विनी:

- ◆ 38 वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक मशाल, जिसका नाम तेजस्विनी है, शक्ति, प्रेरणा और उत्कृष्टता की निरंतर खोज का प्रतिनिधित्व करती है।
- ◆ यह मशाल उत्तराखंड में खेल की भावना और प्रतिस्पर्धा की ज्योति को विस्तारित करेगी, साथ ही राज्य और राष्ट्र को खेल के प्रति एकजुट करेगी।
- ◆ उत्तराखंड के पहाड़ों की भव्यता और वहाँ के लोगों की जीवंत ऊर्जा को प्रतिबिंबित करने के लिये डिजाइन किया गया है।
- ◆ तेजस्विनी उत्कृष्टता और एकता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
- ◆ इसकी चमकदार रोशनी उत्तराखंड के एथलीटों के लिये उज्वल भविष्य का प्रतीक है, जो उन्हें महानता हासिल करने के लिये प्रेरित करती है और साथ ही गर्व और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देती है।

हिमालयन मोनाल



- हिमालयन मोनाल, जिसे इम्पेयन मोनाल या इम्पेयन तीतर के नाम से भी जाना जाता है, तीतर परिवार, फासियानिडे का एक पक्षी है।
- यह उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसे 2018 में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिये शुभंकर के रूप में चुना गया है।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार हिमालयन मोनाल अनुसूची-I पक्षी है तथा IUCN द्वारा इसे न्यूनतम चिंताजनक (LC) पक्षी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता नियम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने **समान नागरिक संहिता (UCC)** के नियमों को मंजूरी दे दी है और जनवरी 2025 के अंत तक कानून के लिये राजपत्र अधिसूचना जारी करने की योजना है, जिससे इसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा।



UNIFORM CIVIL CODE

All sections of the society irrespective of their religion shall be treated equally according to a National Civil Code - the Uniform Civil Code.

THEY COVER AREAS LIKE


Marriage


Divorce


Maintenance


Inheritance


Adoption


Succession of Property

It is based on the premise that there is necessarily no connection between religion and personal law in a civilized society.

"UCC refers to a common set of laws governing civil rights of every citizen."
Article 44 of Directive Principles sets duty of state for implementing UCC.

TIMELINE

1954: Passage of Special Marriage Act provides permission of civil marriage above any religious personal law.

1956: Hindu code bill passed dividing personal laws in:
- Common Indian Citizen.
- Muslim Community.

1986: Rajiv Gandhi government's law in Shah Bano case widens the difference in civil rights.

2003: Then President Dr. Abdul Kalam supported UCC.

2015: Supreme court asserted the need of UCC.

The dialogue for UCC was started by the Law Commission in the year 2016

मुख्य बिंदु

● UCC के प्रमुख प्रावधान:

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



इष्टि लर्निंग
ऐप



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

नोट :

- ◆ फरवरी 2024 में उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता (UCC) आदिवासी समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखती है।
- ◆ यह हलाला, इद्दत और तलाक जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाता है, जो **मुस्लिम पर्सनल लॉ** के तहत प्रथाएँ हैं।
 - यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में **समान अधिकार प्राप्त हों**।
- ◆ संहिता में **विवाह और तलाक के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है**, जिसका अनुपालन न करने पर सरकारी लाभों से वंचित होना पड़ेगा।
- ◆ **अपंजीकृत लिव-इन संबंधों** के लिये कड़े प्रावधान मौजूद हैं, हालाँकि ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाता है।
- **कार्यान्वयन उपाय:**
 - ◆ सरकार ने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार अधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और लिव-इन रिलेशनशिप की समाप्ति के पंजीकरण के लिये एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया है।
 - ◆ नागरिक अपने डेटा और आवेदन की स्थिति को मोबाइल फोन या घर से देख सकते हैं।
 - ◆ सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) को ऑनलाइन पंजीकरण के लिये अधिकृत किया गया है।
 - इंटरनेट सुविधा से वंचित दूरदराज के क्षेत्रों में CSC एजेंट घर-घर जाकर पंजीकरण सेवाएँ प्रदान करेंगे।
 - ◆ सरलता और सुविधा के लिये ईमेल और एसएमएस के माध्यम से **आधार-आधारित पंजीकरण** और ट्रैकिंग की शुरुआत की गई है।
 - ◆ ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण तंत्र भी स्थापित किया गया है।

केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)** ने केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य (KWLS) के पास स्थित पोखनी में कृषि भूमि पर **सोपस्टोन खनन** की अनुमति देने के उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव को रद्द कर दिया।

मुख्य बिंदु

- **वन्यजीव अभयारण्य और लुप्तप्राय प्रजातियाँ:**
 - ◆ केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य हिमालयी कस्तूरी मृग और हिमालयी तहर जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, दोनों को **IUCN रेड लिस्ट** में सूचीबद्ध किया गया है।
- **पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) दिशानिर्देश:**
 - ◆ हालाँकि अभयारण्य के **पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)** की सटीक सीमाओं को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि **परिभाषित सीमाओं के अभाव में संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र को ESZ माना जाता है**।
- **सोपस्टोन खनन का प्रस्ताव:**
 - ◆ वर्ष 2023 में, उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के ESZ के भीतर स्थित पोखनी में सोपस्टोन खनन की अनुमति देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
कलासरुम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- पर्यावरणविदों की प्रतिक्रिया:
 - ◆ पर्यावरणविदों ने इस अस्वीकृति को अभयारण्य और उसके आस-पास के क्षेत्रों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
 - ◆ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह निर्णय खनन कार्यों से क्षेत्र की पारिस्थितिकी और स्थानीय निवासियों को होने वाले खतरों के प्रति जागरूकता को दर्शाता है।
- उत्तराखंड में अनियमित खनन पर चिंताएँ:
 - ◆ अनियमित खनन गतिविधियों, विशेषकर कुमाऊँ के बागेश्वर जिले में, पर बढ़ती चिंताओं के कारण ऐसे कार्यों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया गया है।
 - ◆ उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट से पता चला है कि खनन के कारण भारी नुकसान हुआ है, जिसमें 11 संवेदनशील गाँवों के 200 घरों, सड़कों और कृषि क्षेत्रों में दरारें आ गई हैं।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)

- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एक वैधानिक बोर्ड है जिसका गठन आधिकारिक तौर पर वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत वर्ष 2003 में किया गया था।
- इसने 1952 में स्थापित भारतीय वन्यजीव बोर्ड का स्थान लिया।
- NBWL के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और यह वन्यजीवों और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिये जिम्मेदार है।
- बोर्ड की प्रकृति 'सलाहकार (Advisory)' है और यह केवल वन्यजीव संरक्षण के लिये नीति निर्माण पर सरकार को सलाह दे सकता है।
- यह सभी वन्यजीव संबंधी मामलों की समीक्षा तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में और उसके आसपास की परियोजनाओं के अनुमोदन के लिये एक सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है।
- NBWL की स्थायी समिति की अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री करते हैं।
 - ◆ स्थायी समिति संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों या उनके 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी परियोजनाओं को मंजूरी देती है।

उत्तरकाशी में भूकंप

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रिक्टर पैमाने पर 3.5 तीव्रता का भूकंप आया।

- यह भूकंप, जो 5 किमी. की गहराई पर आया, भूकंपीय घटनाओं की एक शृंखला का हिस्सा है, इससे पहले म्याँमार में 4.8 तीव्रता का एक और भूकंप आया था।

मुख्य बिंदु

- उत्तरकाशी और भूकंपीय संवेदनशीलता:
 - ◆ उत्तरकाशी हिमालयी भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण यह भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
 - ◆ इस क्षेत्र में पहले भी विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं, जिनमें 1991 में उत्तरकाशी भूकंप (6.8 तीव्रता) और 1999 में चमोली भूकंप शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



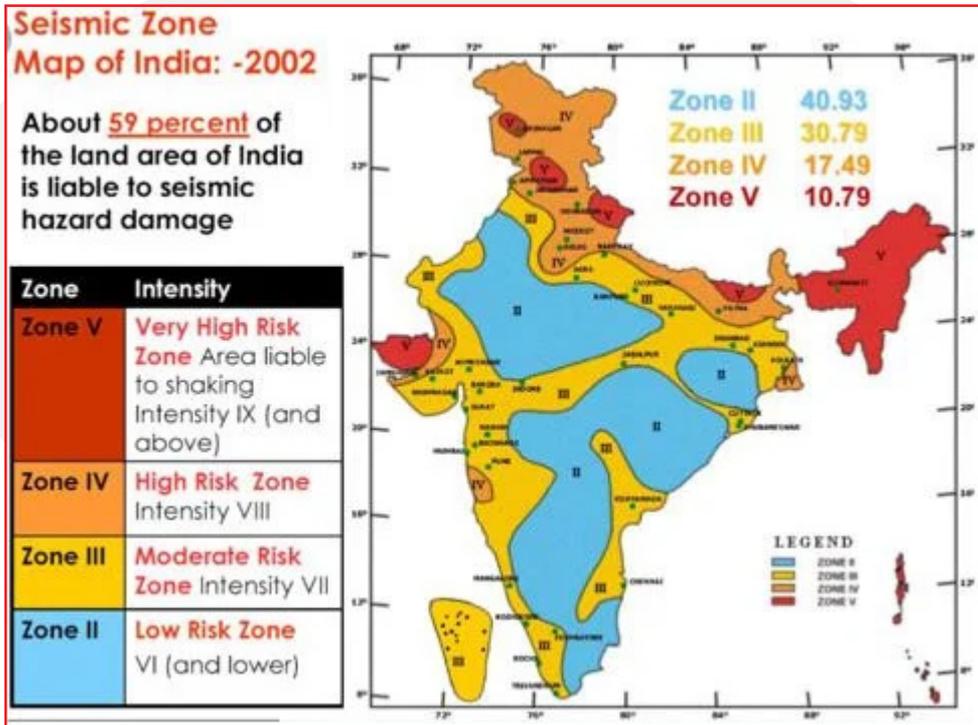
दृष्टि लर्निंग
ऐप



- भूवैज्ञानिक कारक और भेद्यता:
 - ◆ भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव के कारण यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय है।
 - ◆ अनियंत्रित निर्माण और वनों की कटाई ने स्थिति को और खराब कर दिया है, जिससे बड़े भूकंप की स्थिति में विनाश का संकट बढ़ गया है।
 - ◆ उत्तरकाशी और आसपास के शहर जैसे देहरादून, नैनीताल और मसूरी घनी जनसंख्या वाले हैं, जिससे भूकंपीय घटनाओं के दौरान संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

भूकंप

- परिचय:
 - ◆ भूकंप पृथ्वी की सतह का कंपन है जो पृथ्वी की सतह के नीचे ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण होता है।
 - ◆ इस प्राकृतिक घटना से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जो पृथ्वी के सभी दिशाओं में विस्तारित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप जमीन में हलचल होती है।



- भूकंप से संबंधित प्रमुख शब्द:
 - ◆ हाइपोसेन्टर: पृथ्वी की सतह के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है।
 - ◆ अधिकेंद्र (एपिसेंटर): पृथ्वी की सतह पर हाइपोसेन्टर के ठीक ऊपर स्थित वह बिंदु, जहाँ सबसे अधिक तीव्र कंपन महसूस किया जाता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ भूकंप के प्रकार:
 - भ्रंश क्षेत्र: वे भूकंप जो पृथ्वी की पपड़ी में भ्रंश रेखाओं के साथ होने वाली हलचल के कारण आते हैं।
 - टेक्टोनिक भूकंप: पृथ्वी की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।
 - ज्वालामुखीय भूकंप: ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण, आमतौर पर पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा की गति के कारण।
 - मानव-जनित भूकंप: मानवीय गतिविधियों, जैसे खनन या जमीन में तरल पदार्थ डालने से उत्पन्न भूकंप।
- ◆ भूकंप मापने के पैमाने
 - परिमाण पैमाना:
 - ◆ भूकंप की तीव्रता से तात्पर्य उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा से है। इसे रिक्टर स्केल का उपयोग करके मापा जाता है, जो 0 से 10 तक होता है, जिसमें प्रत्येक संख्या आयाम में दस गुना वृद्धि दर्शाती है। यह भूकंप की ताकत का एक माप प्रदान करता है।
 - तीव्रता पैमाना:
 - ◆ भूकंप की तीव्रता का अर्थ है भूकंप के झटके और उससे होने वाली क्षति। इतालवी भूकंप विज्ञानी ग्यूसेप मर्कली द्वारा विकसित मर्कली तीव्रता पैमाना 1 से 12 तक होता है, जिसमें उच्च संख्या अधिक गंभीर झटकों और विनाश का संकेत देती है।

एशियाई जलपक्षी जनगणना

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड के देहरादून जिले के आसन आर्द्रभूमि में स्वयंसेवकों ने पक्षी गणना अभियान के दौरान 117 विभिन्न प्रजातियों के 5,225 पक्षियों की पहचान की।

प्रमुख बिंदु

- आयोजन के बारे में:
 - ◆ पक्षी गणना अभियान का आयोजन 35 प्रतिभागियों की एक टीम द्वारा किया गया था, जिन्हें पाँच समूहों में विभाजित किया गया था।
 - ◆ इसका उद्देश्य आसन आर्द्रभूमि में घरेलू और प्रवासी दोनों पक्षियों की आबादी की निगरानी करना था।
 - ◆ टीमों ने आसन झील, यमुना और आसन नदियों, शिवालिक पर्वत शृंखला और आसपास के संरक्षित वनों सहित स्थानों पर व्यापक पक्षी गणना की।
- सर्वेक्षण और कार्यप्रणाली:
 - ◆ 150 से अधिक स्वयंसेवकों और वन कर्मचारियों ने जलपक्षियों की गणना और अन्य पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करने के लिये पूर्व-निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 23 स्थलों का सर्वेक्षण किया।
 - ◆ पर्यवेक्षकों ने दलदलों और आर्द्रभूमियों के आसपास पक्षियों के व्यवहार और गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया।
- नागरिक विज्ञान पहल:
 - ◆ एशियाई जलीय पक्षी गणना उत्तराखंड के 23 आर्द्रभूमि स्थलों पर एक साथ की गई।
 - ◆ इस पहल को उत्तराखंड वन विभाग का समर्थन प्राप्त था और इसमें विभिन्न गैर-सरकारी संगठन (NGO) भी शामिल थे।

आसन संरक्षण रिजर्व

- परिचय:
 - ◆ आसन संरक्षण रिजर्व आसन नदी के किनारे 444 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो देहरादून जिले में यमुना नदी के साथ संगम तक फैला हुआ है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ वर्ष 1967 में निर्मित आसन बैराज के कारण बाँध के ऊपर गाद जमा हो गई, जिससे पक्षियों के लिये अनुकूल आवास निर्मित हो गए।
- जैवविविधता और प्रजातियाँ:
 - ◆ यह रिजर्व पक्षियों की 330 प्रजातियों का आवास है, जिनमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय लाल सिर वाला गिब्ब, सफेद पूंछ वाला गिब्ब और बेयर पोचर्ड शामिल हैं।
 - ◆ इस स्थल पर लाल कलगी वाले पोचर्ड और रूडी शोल्डर की जैवभौगोलिक आबादी का 1% से अधिक हिस्सा दर्ज है।
 - ◆ गैर-पक्षी प्रजातियों में 49 मछली प्रजातियाँ शामिल हैं, जिनमें लुप्तप्राय पुट्टर महाशीर भी शामिल है।

उत्तराखंड ने UCC लागू किया और पोर्टल लॉन्च किया

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया, जिससे यह स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया तथा गोवा के बाद दूसरा राज्य बन गया।

• नव-प्रवर्तित UCC पोर्टल ने व्यक्तियों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके तथा प्रत्यक्ष गवाह सत्यापन प्रक्रिया से गुजरकर अपने विवाह को ऑनलाइन पंजीकृत करने में सक्षम बनाया है।

मुख्य बिंदु

- विशेषताएँ:
 - ◆ फरवरी 2024 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित UCC विधेयक हलाला, इद्दत और तलाक (मुस्लिम पर्सनल लॉ में विवाह और तलाक से संबंधित प्रथाएँ) जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाता है।
 - ◆ UCC विवाह, तलाक और लिव-इन संबंधों के ऑनलाइन पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है।
 - ◆ इस उद्देश्य के लिये एक सरकारी पोर्टल बनाया गया है, जिस पर लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपनी वसीयत भी अपलोड कर सकते हैं।
- ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया: UCC पोर्टल पर व्यक्तियों को जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र और जीवनसाथी का विवरण सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, दो गवाहों, या तो माता-पिता या स्थानीय अभिभावकों को लाइव वीडियो के माध्यम से गवाही देनी होगी।
 - ◆ पोर्टल में AI-आधारित अनुवाद सेवा है जो सामग्री को अंग्रेजी सहित 22 भाषाओं में अनुवाद करेगी।
- मुख्यमंत्री का समर्थन: CM पुष्कर सिंह धामी ने भी UCC पोर्टल पर अपनी शादी का पंजीकरण कराया और सोशल मीडिया पर अपना प्रमाण-पत्र साझा करते हुए आश्वासन दिया।

समान नागरिक संहिता

- UCC: परिचय
 - ◆ समान नागरिक संहिता (UCC) को संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के भाग के रूप में रेखांकित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार को पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिये समान नागरिक संहिता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ हालाँकि, इसका कार्यान्वयन सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
- गोवा में UCC:
 - ◆ गोवा 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता का पालन करता है। 1962 के गोवा, दमन और दीव प्रशासन अधिनियम ने इसे औपनिवेशिक युग के नागरिक संहिता को बनाए रखने की अनुमति दी।

38वें राष्ट्रीय खेलों के लिये अवसंरचना का विकास

चर्चा में क्यों ?

राजीव गाँधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को रायपुर और देहरादून के बीच जोड़ने वाली सड़कों को अधिक प्रभावी ढंग से यातायात प्रबंधन के लिये चौड़ा किया जाएगा।

- यह निर्णय 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान उत्पन्न हुए गंभीर यातायात जाम के पश्चात लिया गया है।

मुख्य बिंदु

- भविष्य के आयोजनों पर विचार: चूँकि भविष्य में स्टेडियम में और अधिक खेल आयोजन आयोजित किये जाएँगे, इसलिये सरकार का लक्ष्य अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) में सुधार और यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है।
- राष्ट्रीय खेल समापन समारोह: समापन समारोह 14 फरवरी, 2025 को निर्धारित है।
- राष्ट्रीय खेल 2025:
 - ◆ 38वें संस्करण में, राष्ट्रीय खेल, जो कि ओलंपिक से प्रेरित भारत का बहु-खेल आयोजन है, में 28 राज्यों, आठ केंद्र शासित प्रदेशों और सेना खेल नियंत्रण बोर्ड (SSCB) के खिलाड़ी 32 विभिन्न खेलों में पदक के लिये प्रतिस्पर्द्धा करेंगे।
 - ◆ वर्ष 2025 के राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत 26 जनवरी को ट्रायथलॉन स्पर्द्धाओं के साथ हुई।
 - ◆ राष्ट्रीय खेलों के प्रत्येक संस्करण के समग्र विजेता को राजा भल्लिंद्र सिंह टूँफ़ी से सम्मानित किया जाता है।
 - ◆ चैंपियन राज्य का निर्धारण, प्रतियोगिताओं में अंतिम स्थान के आधार पर अर्जित अंकों के आधार पर किया जाता है।
 - ◆ राष्ट्रीय खेल 2025 में भारत के कुछ शीर्ष एथलीट भाग लेंगे, जिनमें ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन (मुक्केबाज़ी), स्वप्निल कुसाले, सरबजोत सिंह और विजय कुमार (निशानेबाज़ी) शामिल हैं।

उत्तराखंड में वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य वन संरक्षक (CCF) को अत्यधिक संवेदनशील जिलों में वनाग्नि के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।

मुख्य बिंदु

- अग्नि नियंत्रण हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति:
 - ◆ वन विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारियों को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।
 - ◆ उनकी भूमिका बेहतर अग्नि प्रबंधन के लिये जिला स्तर पर संसाधनों और विभागों का समन्वय करना है।
 - ◆ जिला स्तर पर प्रबंधन, नियंत्रण, निगरानी, सहयोग और समन्वय को दृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- अग्नि-पूर्व मौसम की तैयारियाँ:
 - ◆ उत्तराखंड वन विभाग ने वनों में आग लगने के मौसम से पहले नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के लिये एक कार्यालय आदेश जारी किया है।
 - ◆ नोडल अधिकारी अग्नि प्रबंधन तैयारियों और जिला स्तरीय नियंत्रण उपायों की समीक्षा करेंगे।
- अग्नि नियंत्रण में सामुदायिक भागीदारी:
 - ◆ इसके साथ ही, वन अग्नि नियंत्रण एवं प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिये उत्तराखंड वन विभाग अल्मोड़ा वन प्रभाग के अंतर्गत राज्य के सभी प्रभागों में 'शीतलाखेत' मॉडल को दोहराने के लिये फील्ड कर्मियों, राज्य पर्यावरण प्राधिकरण (SEA) और वन अग्नि प्रबंधन समितियों के साथ अनुसंधान कर रहा है।
 - ◆ अल्मोड़ा वन प्रभाग के अंतर्गत विकसित 'शीतलाखेत' मॉडल को राज्य के सभी प्रभागों में अपनाया जा रहा है।

जंगल की आग (वनाग्नि)

- वन की आग को झाड़ी या वनस्पति की आग या वनाग्नि भी कहा जाता है, इसे किसी प्राकृतिक सेटिंग जैसे जंगल, चरागाह, ब्रशलैंड या टुंड्रा में पौधों के किसी भी अनियंत्रित और गैर-निर्धारित दहन या जलने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो प्राकृतिक ईंधन का उपभोग करता है और पर्यावरणीय स्थितियों (जैसे, हवा, स्थलाकृति) के आधार पर विस्तारित होता है।
- जंगल में लगी आग को जलाने के लिये ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा स्रोत जैसे तीन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है।





दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :